

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग- 5

देहरादून,

दिनांक: 9 जून, 2016

विषय: बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के निर्माण कार्यों विस्तृत आगणन की अनुमोदित लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1566/XXVIII-5-2014-176/2009 दिनांक 12.09.2014 के कम में इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 200 शैय्यायुक्त बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत ₹6304.28 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹4085.85 लाख तथा अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों के लिए ₹2238.63 लाख) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इस वित्तीय वर्ष में ₹100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. दिनांक 21 अक्टूबर, 2011 को आयोजित व्यय वित्त समिति में बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के निर्माण हेतु आवासीय भवनों की लागत ₹4155.64 लाख पर दी गई व्यय वित्त समिति की सहमति स्थल परिवर्तन के कारण एवं गतिमान व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
2. उक्त के अतिरिक्त पूर्व में जारी सम्यक शासनादेशों के अन्तर्गत इस परियोजना हेतु जारी धनराशि को उक्त अनुमोदित लागत ₹6304.28 लाख में अवश्यमेव समायोजित किया जाय।
3. शासनादेश संख्या-1609/XXVIII-5-2014-176/2009 दिनांक 30.09.2014 द्वारा प्रदत्त ₹99.37 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-163/XXVII (7)/2008 दिनांक 22 मई, 2008 के अनुरूप समायोजित कर लिया जाय।
4. वर्तमान परिदृश्य में Energy Efficient Buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवन को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy Efficient बनाये जाने तथा इस हेतु Buildings के सम्बन्ध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस सम्बन्ध में Tata Energy Research Institute (TERI) द्वारा जारी Guide line/Representative Designs of Energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्रावधान किया जाये, यथा सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।
6. Water Harvesting का समुचित प्रावधान किया जाय।
7. निर्माण सामग्री यथा Bricks, Cement, Steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण करा लिया जाय।
8. Electrical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि, Plumbing items जैसे Bath fittings, geyser, water tank, pipes आदि, Toilet items, wood items आदि की Market survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में

(2)

रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय कर पूर्व में ही Brand Name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेंट मदों की लागत ₹3.00 लाख से अधिक हो तो अधिप्राप्ति नियमावली-2008 (यथासंशोधित 2015) के अनुसार कार्यवाही की जाय।

9. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई हैं एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगे, जो अपरिहार्य मदें हैं। उदाहरणार्थ, वाटरप्रूफिंग की मदें अलग से आगणन में ली गई हैं। यह सही है कि यह मद डी0एस0आर0 में है लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन मदों को विशेष रूप से रखेंगे।
10. आगणन में कन्टीजेंसी मद में केवल 02 प्रतिशत धनराशि देय होगी।
11. आगणन में प्रावधानित सौक पिट तथा सेप्टिक टैंक के स्थान पर बायोडाईजेस्टर आधारित ट्रीटमेंट का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय।
12. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
13. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
14. अनुसूचित योजना/निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियत किये गये लक्ष्यों व उद्देश्यों के क्रियान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाय तथा निर्माण कार्यों की लागत एवं समय वृद्धि किसी भी दशा में न होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाय।
15. महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना की निर्धारित अवधि, वित्तीय/भौतिक लक्ष्यों एवं लक्षित आउटपुट व आउटकम के अनुसार ही प्रगति हो रही है और उसमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। योजना की नियमित व आवधिक समीक्षा समय-समय पर कर ली जाय।
16. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्ज से ही वहन किया जायेगा।
17. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्यदायी संस्था के साथ नियमानुसार एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाय।
18. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय-व्ययक वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, आयोजनागत-00 01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 23-बेस चिकित्सालय, पिथौरागढ़ का निर्माण 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-2047/XXVII(1)/2016 दिनांक 07 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

संलग्न: ऑलटमेंट आई.डी. संख्या-S1606120115

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

(3)

संख्या-704(1)/XXVIII-5-2016-176/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊं।
6. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
8. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पिथौरागढ़।
9. परियोजना प्रबन्धक, अवस्थापना विकास निगम, देहरादून/पिथौरागढ़।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(Signature)
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।